खंड–११ संख्या–२४

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–२ कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित।)

बुधवार, तिथि १९ मार्च, १९७५

विषय-सूची

	पृष्ठ
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा। ..	१
विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प :	
बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) अध्यादेश, १९७५ (अस्वीकृत)। ..	२–३२
बिहार विधान-परिषद् द्वारा यथापारित बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) विधेयक, १९७५ के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा। ..	३२–३७
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :	
(क) राज्य में बढ़ती हुई चोरी, डकैती एवं राहजनी से उत्पन्न स्थिति। ..	३७–३९

उपाध्यक्ष— माननीय सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद का कटौती प्रस्ताव है। अगर उसे लेता हूँ तो व्यापक नहीं होता है, क्योंकि राज्यमंत्री के टेलीफोन आदि के खर्चा के बारे में है।

श्री अम्बिका प्रसाद— कार्यालय व्यय के बारे में है।

उपाध्यक्ष— उसमें दिया हुआ है कि उपबन्धित राशि के समाप्त हो जाने के कारण दूरभाष एवं अन्य खर्चा। आप पहले मूव कर दीजिये मैं जेनरल बना देता हूँ।

श्री अम्बिका प्रसाद— उपाध्यक्ष महोदय ? मैं मूव कर देता हूँ आप जेनरल डिसकशन करा दीजिये। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यमंत्रीगण कार्यालय व्यय के लिये दो लाख ५० हजार....

श्री कमलदेव नारायण सिन्हा— माननीय सदस्य श्री अम्बिका बाबू ने कहा कि मैं मूव कर देता हूँ आप जेनरल डिसकशन करा दीजिये। लेकिन उसका दायरा सीमित हो जायगा और सिर्फ टेलीफोन आदि पर ही डिसकशन हो सकता है। इसलिये पहले आप इसका निर्णय कर लीजिये और जेनरल डिसकशन टोटल विभाग पर करा दीजिये।

उपाध्यक्ष— इनको कट मोसन मूव करने दिया जाय क्योंकि अन्य बकाया भी दिया गया है, उसमें आ जायगा।

श्री कमलदेव नारायण सिन्हा— टोटल डिमान्ड को डिसकशंस में रखें तो अच्छा होगा।

श्री अम्बिका प्रसाद— टेलिफोन, अन्य बकाया कार्यालय में आ जाता है।

उपाध्यक्ष— खींच-तीर करके हो सकता है।

कटौती प्रस्ताव : इस खर्च के दुरूपयोग पर विचार-
विमर्श करने के लिए।

श्री अम्बिका प्रसाद— मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"राज्य मंत्रिगण कार्यालय व्यय के लिये २,५०,००० रुपये का उपबन्ध लोपित किया जाय"।

★श्री एस० के० राय––उपाध्यक्ष महोदय, श्री अम्बिका प्रसाद द्वारा विनियोग विधेयक पर लाये गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन की बातें आये दिन होती रहती है। सदन में और सदन से बाहर वर्षों से इन बातों की जोरों से चर्चा होती रही है कि बिहार की बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। प्रति व्यक्ति आमदनी करीब-करीब देश के सभी राज्यों से कम है। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने पिछले वर्षों में कौन-कौन से कदम उठाये––यहाँ यह विचारनीय है। यह सही है कि आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन के साथ आर्थिक विषमता को भी पैदा करता है, जिसका भुक्तभोगी हमारा समाज है। यह सही है कि यह कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की बहुसंख्यक जनता कृषि पर जीवन निर्वाह करती हैं। १९७१ की जनगणना के मुताबिक यहाँ ८०.४ फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं; जबकि पूरे देश में यह औसत ६८.५६ फीसदी का है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कृषि का विकास समुचित ढंग से न होगा तब तक न तो हमारा आर्थिक विकास होगा और न तो जीवन का ही विकास होगा। कृषि का विकास बिहार के जीवन के विकास से सम्बन्धित है। अब सवाल यह उठता है कि कृषि के विकास की दिशा में सरकार ने कौन-सा कारगर कदम उठाया। महोदय, आप इस बात से अवगत होंगे कि बिहार उन राज्यों में से एक है, जहाँ पर वारेनहेस्टिंग के समय में बन्दोबस्ती के माध्यम से अंग्रेजों ने अपना सामाजिक आधार मजबूत करने के लिये एक जमीदार वर्ग का सृजन किया। बिहार में जमींदारी उन्मूलन तो हुआ, परन्तु जमींदार वर्ग का उन्मूलन अभी भी बाकी है। यहाँ की कृषि-व्यवस्था का चरित्र आज भी अर्धसामंती है। बिहार का कुल क्षेत्रफल ४५० लाख एकड़ है; जबकि कुल खेती योग्य जमीन का क्षेत्रफल केवल २०५ लाख एकड़ है और सभी सिंचाई साधनों के माध्यम से हम केवल ५३ लाख एकड़ भूमि की निश्चित सिंचाई कर सकते हैं। जमीन की मलकीयत अभी भी जमींदारों के हाथ में है। देहाती कुल आबादी का भूमिहीन ३८.९ परसेन्ट, गरीब किसान ३० परसेन्ट, मध्यम किसान २१.१ परसेन्ट धनी किसान ७ परसेन्ट जमीदार ३ परसेन्ट। आज भी ८० फीसदी जोतें पाँच एकड़ से कम की है एवं २० फीसदी जमीन केवल १० फीसदी लोगों के हाथ में है। आज

भी वे मालिक बने हुए है। ऐसी हालत में कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। महोदय, जब तक इस प्रांत में कृषि का विकास नहीं होगा तब जन के जीवन का विकास नहीं हो सकता है। आर्थिक पिछड़ापन का यह मुख्य कारण है कि हम सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, जबकि यहां सारे सिंचाई के साधन मौजूद है। यहाँ सारे सिंचाई के साधन के बावजूद ५३ लाख एकड़ से ज्यादा समुचित और निश्चित सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। मैं दूसरे राज्यों को तुलनात्मक दृष्टि से देखता हूँ तो कृषि, सिंचाई और बिजली में जो भी खर्च हुआ है उससे ज्यादा है, लेकिन उससे जो विकास का काम होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। आप जानते हैं कि कोयला हमारे देश में सबसे ज्यादा है और कोयले के माध्यम से हम अधिक-से-अधिक बिजली पैदा कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाये हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि साढ़े बारह प्रतिशत गाँव में हम बिजली दे पाए हैं। ११ मार्च, १९७४ तक ९७ हजार सिंचाई के पम्पों में हम बिजली दे पाये हैं; जबकि पूरे देश में साढ़े चौबीस लाख सिंचाई पम्पों को बिजली दी जा चुकी थी। आज भी बिजली की खपत ३८ कीलोवाट प्रति घंटा है और सारे हिन्दुस्तान के आधार पर ९६ कीलोवाट प्रति घंटा है। महोदय, केन्द्रीय सरकार भी इसमें कम जिम्मेवार नहीं है। राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों ने भी भरपूर पक्षपात किया है। जैसा कि ३१ दिसम्बर, १९७३ में बिहार राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों का कुल जमा ४४९ करोड़ रुपये थे, जबकि उनके द्वारा दिया गया ऋण एवं लगायी गयी पूंजी सिर्फ १९९ करोड़ रुपये की थी। इस प्रकार कुल जमा राशि के अनुपात में ऋण एवं लागत पूंजी केवल ४१.४६ प्रतिशत थी; जबकि पूरे देश में यह अनुपात ८५ प्रतिशत थी। इससे साफ जाहिर होता हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जमा की गई रकम दूसरे राज्यों में लगायी जाती है। यहाँ पर जो पूंजी लगायी भी जाती है उसका फायदा भी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से चन्द मुट्ठी भर लोग ही उठाते हैं।

महोदय, आज सभी लोग महंगाई के शिकार हैं। कल वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकार इसके लिए कारगर कदम उठा रही है। १९७३-७४ वर्ष में थोक मूल्यों के सूचक अंक में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह गिरावट इनफ्लेशन को नियंत्रण करने की दिशा में सरकार की ओर से उठाये

गये कदमों की वजह से हुई । परन्तु ऐसी बात नहीं है । यह गिरावट तस्करों, गल्लाचोरों, जमाखोरों एवं चोर बाजारियों के गोदामों और तिजोरियों पर छापा मारने एवं उन्हें मिसा में बन्द करने की वजह से हुई है । उनको मिसा में बन्द किया गया, नतीजा हुआ कि मूल्यों में कमी आयी । सरकार सीमित दायरे में जाकर कारकर कदम उठा, जनता का सहयोग ले, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दें, निकाले गये सामानों को नियंत्रित दर पर वितरित करावे, तब लोगों को राहत मिलेगी । सरकार चोर बाजारी करने वाले को एन्टीसिपेटरी बेल दे देती है । इसमें कुछ संशोधन किया जाय । जिससे कि वे जेल से नहीं निकल सकें । सरकार को स्थिति को नियंत्रित करने के लिये, महंगाई को रोकने के लिये बहुत से कारगर कदम उठाने की जरूरत है । इसके लिये सरकार गेहूँ, चावल, मोटा अनाज, करूआ तेल, किराशन तेल, मोटा कपड़ा तथा जीवन रक्षक दवाओं आदि का थोक व्यापार अपने हाथ में ले । इन सामानों का वितरण शहरी एवं देहाती इलाकों में, खानगी और सार्वजनिक क्षेत्रों के औद्योगिक अधिष्ठानों में सस्ते गल्ले की दूकानों की जन वितरण प्रणाली के माध्यम से हो । बाजार योग्य तमाम अतिरिक्त पैदावार को ग्रैडेड लेभी के आधार पर सीधे उत्पादकों से उगाह लिया जाय और उसी तरह अन्य जीवनोपयोगी सामानों के भण्डारों को सीधे मिलों एवं कारखानों से ले लिया जाय । सबसे बड़ी बात यह है कि गल्ला चोरों को राहत भ्रष्ट औफिसरों द्वारा मिलता है, उसको कम करायें ।

श्री जय प्रकाश नारायण के सम्पूर्ण क्रान्ति के विषय में हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है कि मँहगाई, भ्रष्टाचार बेरोजगारी, ये सारी चीजें जो हैं, वे पूंजीवादी व्यवस्था की ओर से हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी, तब तक यह मूलतः दूर नहीं हो सकती है । चुनाव और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने से कुछ सुधार हो सकता है, परन्तु सारी गड़बड़ियाँ दूर नहीं हो सकी । भ्रष्टाचार एवं बेरोजगार एवं मँहगाई पूंजीवादी व्यवस्था की उपज है । इतिहास से हमें इस बात की मदद नहीं मिलती है कि जहाँ पर बालिग मताधिकार है, उस देश को या तो क्रान्तिकारी परिवर्तनों का सामना करना पड़ा हो या मतदान के बहिष्कार का ही । मतदान क्रान्तिकारी है, यदि वह संघर्ष को तीव्र बनाता है तो प्रतिक्रियावादी है, और वह संघर्ष की आग पर पानी डालता

है। आज भी जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति वर्ग संघर्ष की आग पर पानी डालती है। क्योंकि शोषक, शोषक के खिलाफ सैद्धान्तिक संघर्ष नहीं कर सकता है। गल्लाचोर, सट्टेबाज, काला बाजारी, बड़े सामन्त, एकाधिकार, पूंजीपति वर्ग, समझ में नहीं आता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं जो श्री जय प्रकाश के इर्द-गिर्द खड़े हैं। १९७१ का महा-गठबंधन आज दूसरे रूप में जनता के सामने आ गया है। स्वतंत्र, जनसंघी एवं सिंडीकेटियों के सामने श्री जय प्रकाश नारायण पटेलवादी बन जाते हैं, सर्वोदयवादियों के समक्ष गांधीवादी बन जाते हैं और मार्क्सवदियों के सामने अपने को माओवादी घोषित करते हैं। श्री जय प्रकाश नारायण ने पिछले दो-तीन वर्षों में क्या कहा, अगर उस पर आप ध्यान दें तो जे० पी० के उद्देश्य साफ नजर आयेंगे। यदि आर्थिक मसलों पर विचार किया जायगा तो साफ नजर आयेगा। साम्राज्यवादियों के सरगना अमेरिका के प्रति उनकी अगाध भक्ति उनके आज तक के राजनीतिक जीवन में भरपूर पायी गयी है। श्री जय प्रकाश नारायण ने इस चीज की कभी चर्चा नहीं की कि देश के आर्थिक विकास को मजबूत किया जाय। उन्होंने उद्योग में राजकीय क्षेत्र अथवा राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। संविधान में सम्पत्ति के मूल अधिकार सम्बन्धी परिवर्तनों का विरोध किया। अन्न के थोक व्यापार के अधिग्रहण का विरोध किया। सोवियत संघ के साथ भारत के आर्थिक राजनीतिक संबंधों का विरोध किया। धनवाद की मिटिंग में गये थे और वे रात में एक खान मालिक के रेस्ट हाउस में ठहरे। खान मालिक के यहाँ खाना खाया और दूसरे दिन उन्होंने भाषण दिया और कहा कि अगर मैं सक्षम होउँगा कांग्रेसी हुकुमत को अपदस्थ करने में तो मैं खदान मालिकों को उनके पुराने जो खदान हैं, उनको मैं सुपुर्द कर दूँगा। उन्होंने मुक्त व्यापार की सराहना की, जिससे मुनाफाखोरों को मनमाना दाम तय करने का अधिकार रहे। उन्होंने चीन जनवादी सरकार का विरोध नहीं किया। अमेरिकी साजिस द्वारा चिल्ली निर्वाचित सरकार को जबरदस्ती अपदस्थ करने और वहाँ के लोकप्रिय राष्ट्रपति आलन्डे की निर्मम हत्या के खिलाफ मुंह बन्द कर लिया। उन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिकी कुचक्रों के खिलाफ हल्की आवाज भी नहीं उठायी। जैसे दिआगो गार्सिया में अमरिकी फौजी अड्डे के

खिलाफ आवाज नहीं उठायी। श्री जय प्रकाश नारायण के पिछले तीन चार वर्षों के भाषण को देखा जाय तो उससे पता चलेगा कि जिस तरह प्रतिगामी शक्तियाँ जनता के असंतोष से फायदा उठाकर जैसे यूरोप में हिटलर, इटली में मुसोलिनी ने आन्दोलन शुरू किया था, उसी तरह से उन्होंने फासिस्ट आन्दोलन शुरू किया है।

(इस अवसर पर श्री कामदेव प्र० सिंह ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, मुझे एक गुप्त खबर मालूम हुई है। हो सकता है कि सरकार के सी० आई० डी० को इस बात की खबर नहीं हो। श्री जय प्रकाश नारायण को मदद देने के लिये इस राज्य के कुछ पदाधिकारियों की एक केन्द्रीय समिति बनी है। इसमें एक क्षेत्रीय समिति छोटानागपुर में बनायी गयी है। इसमें जो केन्द्रीय समिति बनायी गयी है, उसमें सात सदस्य है। लेकिन मुझे पाँच बड़े अधिकारियों का नाम मालूम है।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)— माननीय सदस्य यदि किसी का नाम यहाँ लेते हैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ नाम कहें।

श्री एस० के० राय— मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही इस बात को कह रहा हूँ। प्रधान ज्वाला प्रसाद, चेयरमैन, हाउसिंग, शंकर शरण, वर्क्स कमिश्नर, नन्दकिशोर प्रसाद, ऐडिशनल चीफ इन्जीनियर और छोटानागपुर के डी० आई० जी० श्री नारायण हैं। उत्तर बिहार के संयोजक हैं डी० आई० जी० श्री एस० एन० श्रीवास्तव और शंकर शरण द्वारा चन्दा भेजा जाता है।

सभापति महोदय, दरभंगा जिला बहुत ही उपेक्षित जिला है। यों तो पूरा छोटानागपुर और संथालपरगना ही उपेक्षित है। आप जानते हैं कि धनबाद जिला का रेवेन्यु राज्य में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन उसके हर विकास का काम पीछे पड़ा हुआ है। सड़क के मामले में चाहे वह झरिया बलिया रोड, झरिया-धनबाद रोड हो, कोई भी रोड हो, उनकी हालत दयनीय है। झरिया वाटर बोर्ड, नोटिफाइड एरिया आदि का कारपोरेशन बनाने का प्रस्ताव जो सरकार के सामने पेश है, वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ है। पेय जल की समस्या का समाधान नहीं हो सका। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बहुत ही बुरी है।

पिछले फरवरी में तीन मजदूरों की हत्या हुई और लगातार १२-१४ हत्याएँ हुई हैं। बालकेश्वर राम, रामलखन यादव की हत्या एक सप्ताह बाद हुई। इनको गोली से मार दिया गया। समय-समय पर खबर देने के बावजूद भी, पुलिस तैनात है, मैजिस्ट्रेट है, सी० आर० पी० हैं और वहाँ से एक हजार गज की दूरी पर इस तरह की घटनायें होती हैं और एस० पी० को जिम्मेदारी से वंचित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान दे।

★श्री नगीना राय— समापति महोदय, जो माँग पेश की गई है मैं उसका समर्थन करता हूँ और अम्बिका बाबू ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और ८७-८८ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से अमेरिका जो आज संसार का सबसे बड़ा औद्योगिक देश है, १८६० ई० में वहाँ पर ६५ प्रतिशत आदमी कृषि पर निर्भर करते थे और आज वहाँ जो औद्योगिकरण हुआ हैं ६५ प्रतिशत लोग उद्योग पर और ५ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। आज भारत के औद्योगीकरण की जरूरत है, लेकिन आज बिहार में हमारा सारण जिला में या ओल्ड सारण जिला-सीवन, छपरा और गोपालगंज की आबादी ४६ लाख की है, लेकिन बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इन्डस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया के अन्तर्गत इस जिले का नाम नहीं भेजा है और १० प्रतिशत कैपिटल सबसिडी जो मिलती केन्द्र से वह नहीं मिल पा रही है। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से आग्रह है कि इसकी अनुशंसा करके केन्द्रीय सरकार को भेजे जिस तरह दरभंगा, सहरसा और चम्पारण का है। उत्तर बिहार के सभी जिले औद्योगीकरण के मामले में पीछे है, इसलिये उन सबका नाम आना चाहिये। कृषि के विकास के लिये यहाँ कृषि विश्वविद्यालय खोले गये और पहले ऐसा लगता था कि बिहार को अब पंतनगर की ओर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बना तो उसमें मोटी तनखवाह पाने वाले अफसरों को बहाल किया गया, मगर वह विश्वविद्यालय यह कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि वह इस राज्य को अच्छा बीज दे सकेगा। कृषि के दो अंग हैं, एक शिक्षण और दूसरा अनुसंधान। अनुसंधान के मामले में यह राज्य पीछे है और जरूरत पड़े तो बिहार में २-३ विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा खर्च करना, करोड़ों रुपया खर्च करना अहितकर ही होगा।

अभी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको टाइम वाउण्ड करना चाहिये कि इस राज्य को वे अच्छा बीज दें। राज्य के लिये जहाँ १४४ लाख टन अन्न की जरूरत है वहाँ हम ९० लाख टन गल्ला पैदा करते हैं। १९६२ में हम ६५ लाख टन पैदा करते थे लेकिन आज हम २४ लाख टन पीछे हैं। अगर वढ़िया वीज और खाद दिया जाय तो यह कोई बड़ी खाई नहीं है। इसलिये अप-टू-डेट बढ़िया सीड देकर राज्य को आगे वढ़ा सकते हैं।

दूसरी चीज है, सिंचाई। अभियंताओं की हड़ताल हुई है और सरकार ने उनकी मांगों को माना भी है। लेकिन आज भी सिंचाई को इंजीनियर हेड नहीं करते हैं। सिंचाई आयुक्त के पद पर एक नन-टेकनिकल आदमी है। मैं मानता हूँ कि सामान्य प्रशासन के लिये आई० ए० एस० अफसर अच्छे हैं। लेकिन जहाँ डंम का नक्शा हो, सिंचाई को टेकनिकली देखना हो, उसे टेकनिकल एक्सपर्ट ही अच्छी तरह देख सकते हैं। वंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश ने इस वात को मान लिया है। उन प्रांतों में सिंचाई विभाग को हेंड करते है टेकनिकल एक्सपर्ट लेकिन हमारे यहाँ सिचाई विभाग को हेड कर रहे हैं एक नन-टेकनिकल आदमी। इसलिये यहाँ भी सिंचाई आयुक्त एक इंजीनियर को होना चाहिये। सिंचाई मंत्री सदन में नहीं है। वे प्रगतिशील व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने ठीका के लिये कुछ नियम बनाया है ऐसा कि गंडक का काम वाटर कोर्स के विना रुका हुआ है। दो-चार हजार का कान भी विना टेंडर के नहीं होता है। टेंडर देने के लिये ए, वी और सी तीन कैटेगरी के ठिकेदार हैं। सी क्लास का ठीकेदार वही होगा जो पहले २५,००० रु० का तीन काम कर चुका होगा। इस प्रकार नया आदमी तो टेंडर दे ही नहीं सकता है। जो पहले काम किया हो वही हो सकता है। इसलिये नियम में संशोधन की जरूरत है। छोटे-छोटे काम विना कंट्रेक्ट के ही देना चाहिये जैसे वाटर कोर्स वनाना। ऐसा नियम होना चाहिये कि १५,००० रु० के काम के लिये रजिस्टर्ड ठीकेदार का होना जरूरी नहीं रहे।

दूसरी बात लैंड एक्वीजीशन के पावर के बारे में है। छोटे-छोटे लैंड एक्वीजीशन का काम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करते हैं, अभी उन्हीं को पावर है। उस ऐक्ट को अमेंड करने की जरूरत है। एक्जीक्युटिव इंजीनियर या दूसरे छोटे-छोटे अफसर को आप इसे दीजिये जिसमें वे भी इस काम को कर सकें।

हुजूर, हमारे यहाँ गंडक का काम चल रहा है। कोसी का काम भी चला। एक तरफ जहाँ पहले योजना नहीं थी और वहाँ जो अश्योर्ड इरिगेशन होता था वहाँ प्रोजेक्ट होने के वाद वाटर लौगिंग का प्रोवलेम हो गया है। इस प्रोबलेम के ड्रेनेज के लिये २० करोड़ रुपया रखा गया है, लेकिन अभी तक औरगनाइज नहीं किया गया है। गंडक का पानी आ चुका है और ड्रेनेज का काम चालू नहीं हुआ है जिसके कारण वाटर लोगिंग होता है और फसल बर्बाद होती है। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को शीघ्र चालू करने की जरूरत हैं।

छोटानागपुर के बारे में बराबर इस सदन में बातें उठायी जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पहले डी० बी० सी० को तो दान में दे दिया। कोनार से २ लाख एकड़ जमीन पट सकती है। इसी तरह तिलैया डैम एक बहुत बड़ी योजना पड़ी हुई है। श्री के० एल० राव ने कहा था कि इसके लिये ९ करोड़ की योजना है जिससे गया, नवादा और हजारीबाग के कुछ हिस्से पट सकते हैं। लेकिन इसका विरोध किया गया और बंगाल सरकार से क्लियरेन्स मिल रहा है। दूसरी ओर आप तेनूघाट का पानी वेस्ट बंगाल को दे देते हैं जो शर्मनाक बात है। एक योजना बनाइए जहाँ गंगा है और बक्सर से लेकर भागलपुर तक ६ लाख एकड़ जमीन पटेगी। यह जमीन १२ मील के एरिया में पड़ती है। चौसा में बराज बना दें और ६ लाख एकड़ जमीन पटाने की व्यवस्था करें। सिर्फ ९० करोड़ की यह योजना है।

बजट के द्वारा जो आज सदन से मांग की जा रही है यह बजट सही बजट नहीं है बल्कि एम्पलायी ओरियनटेड बजट है। यह बजट सरकारी नौकरशाही के लिये है किसानों के लिये नहीं, किसानों के बच्चों के लिये नहीं है जो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल का अपना मकान नहीं है, कहीं मकान है तो उसका छप्पर नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे पढ़ते है सरकार को इसके लिये प्रोविजन करना चाहिये। देहातों में जो स्कूल है उसको बनवाना चाहिये। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग जनसम्पर्क विभाग है। सहकारिता के बैंक से किसानों को कर्ज मिलता है और विस्कोमान के माध्यम से उधार खाद मिलता है। केन्द्रीय सरकार ने विस्कोमान को जो १५ करोड़ रुपया दिया था वह वापस मांग रहा है यदि यह वापस दे

देगा तो इसकी पूँजी समाप्त हो जायेगी। नतीजा होगा कि किसानों को उधार खाद मिलना मुश्किल हो जायेगा। बिहार सरकार को इसका विरोध करना चाहिये कि केन्द्र ने जो पन्द्रह करोड़ रुपया बिस्कोमान को दिया था वह वापस न ले, वल्कि कम सूद ले और आगे भी जो रुपया इसे दे उसपर कम ही सूद ले। सरकार जो चकवन्दी की व्यवस्था कर रही है, उसे सभी जिलों में चलाया जाय जिससे यह काम जल्द हो जाय और लोगों को फायदा हो। हमारे गोपालगंज जिला में चार चीनी मीलें हैं और समूचे पुराने छपरा जिले में आठ हैं। यह जिला शुगर प्रोड्यूसिंग जिला है। इसलिये खाद्यान्न के मामले में यह डिफिसिट रहता है, लेकिन फिर भी, वहाँ अभी तक लेवी वसूल किया जा रहा है। हालांकि, सुना है कि सरकार ने बहुत अंश तक इसे वापस ले लिया है और इस सम्बन्ध में सरकार का सरकुलर भी निकल चुका है, लेकिन यह अभी तक हमारे यहाँ नहीं पहुँच सका है जिससे अभी भी लोगों से लेवी वसूला जा रहा है। छोटे-छोटे व्यापारियों से भी वसूला जा रहा है जिसे सरकार ने छूट दे रखी है।

हर जगह और खास कर हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोला गया है उसमें डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा बेड्स और दवा की भी व्यवस्था होनी चाहिये। विद्युत के सम्बन्ध में इस राज्य का दुर्भाग्य है कि देश के सभी राज्यों से इस राज्य में विद्युतीकरण बहुत कम हुआ है। इसके लिये ऐडवान्स प्लानिंग में एक श्री डी० एन० प्रसाद, एक्जीक्युटिव इंजीनियर भेजे गये हैं, जो सब जगह से छाँट दिये गये हैं और जहाँ-जहाँ गये हैं, पीटे गये हैं। ये हमारे यहाँ एक भी काम नहीं करते हैं और ठीका का काम भी अपने भाई-भतीजा को ही दे रहे हैं। इसके लिये हमारे यहाँ के विधायकों ने भी मुख्य मंत्री को लिखकर दिया, लेकिन फिर भी, वह आजतक वहीं बैठा हुआ है। सरकार इस मामले में बिलकुल अनएफेक्टिव साबित हो रही है। सरकार को इसपर ध्यान देकर उसे वहाँ से हटा देना चाहिये। इसके बाद केन सेस का बहुत सा रुपया हमारे जिले में मिल मालिक के पास बाकी पड़ा हुआ है जिसे वे नहीं दे रहे हैं। नतीजा है कि वहाँ एक भी विकास का काम ईख वाले क्षेत्र में नहीं हो रहा है। कानून है कि १४ दिनों में यह रुपया पेमेन्ट हो जायगा, लेकिन आज सात आठ वर्षों से रुपया मिल मालिक के यहाँ बाकी पड़ा है।

सरकार को चाहिये कि ऐसे-ऐसे मिलों को क्रिमिनली प्रोसेक्युट करे और लोगों का तथा केन सेस का रुपया दिलवाकर विकास का काम कराये। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों को आज धड़ल्ले से बगल के जमीन वाले काट-काट कर अपनी जमीन में मिलाते जा रहे हैं जिससे सड़क की चौड़ाई दिनों-दिन कम होती जा रही है। सरकार को इसके लिये कानून बनाकर रोकना चाहिये। सामुदायिक विकास विभाग के जरिये ग्रामीण सड़कों के लिये सरकार को ज्यादा से ज्यादा रुपया देना चाहिये। इसके अलावा गोपालगंज सिवान रोड की चौड़ाई को बढ़ा देना चाहिये जिससे यह नेशनल हाइवे से मिल जाय, क्योंकि बीच में यह सिर्फ २२ मील ही बाकी रह जाती है। लॉ ऐंड आर्डर की स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही हैं, क्योंकि बन्दूक के लाइसेंस मिलने में बड़ी कठिनाई जहाँ एक ओर होती है, वहीं दूसरी ओर गाँव-गाँव में बिना लाइसेंस के बन्दूक हो गये हैं। सरकार बन्दूक की लाइसेंस देने में जिला प्रभारी से लेकर नीचे के दारोगा तक से जाँच कराने के बाद देती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें इतना ज्यादा विलम्ब न करके स्वयं जिलाधिकारी जगह-जगह कैंप करके जांच करके दे दिया करें। आपको लॉ ऐंड आर्डर मेनटेन करने के लिये हाथ पसारने और चिरोरी करने से कुछ नहीं होगा। आपको इसके लिये सख्ती करनी होगी। "शासन न कशीदे से चलती है, न दोहे से चलती है, कड़ी सल्तनत तो लोहे से चलती है"। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

★**श्री उत्तम लाल यादव**— सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री अम्बिका बाबू ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिये करता हूँ कि यहाँ के मंत्रियों के परफोर्मेंस को देखने से मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके परफोर्मेंस से निराशा होती है। जब राजस्व मंत्री बोलने लगते हैं तो एक धड़ल्ले से इतना वादा करते हैं कि लगता है कि ये सब कुछ कर देंगे। सारी जमीन जो फाजिल है उसे बाँट देंगे, जिनको घर की जमीन नहीं है उसे घर के लिये जमीन दे देंगे यानी ये सारी व्यवस्था कर देंगे। परन्तु वास्तव में जो व्यवस्था कर सके हमारे राजस्व मंत्री वह बिलकुल नगण्य है इसलिये मुझे निराशा होती है और आगे भी ये कुछ ऐसा कर सकेंगे यह आशा मुझे नहीं बंधती है।

दूसरे जब हमारे माननीय मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी बोलते है तो वे बहुत ही सुनहला पिक्चर—रोजी पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। मालूम होता है कि सूबे का बहुत बड़ा कल्याण उनके द्वारा होगा। परन्तु क्या कल्याण हुआ है यह देखने को नहीं मिलता है। हमारे दारोगा बाबू हैं, उनकी बात सुनिये तो किस्सा-कहानी कहकर बात समाप्त कर देंगे।

अब मैं सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूँ। पूर्वी कोशी नहर बनी, उससे जितनी जमीन की सिंचाई नहीं हुई उससे अधिक जमीन में पानी का जमाव हो गया। पश्चिमी कोशी नहर का निर्माण हो रहा है, वह निर्माणावस्था में है। अतः अभी से इस पर सरकार को और सिचाई विभाग को ध्यान देना चाहिए जिससे वहाँ भी वाटर लॉगिंग का प्रोबलम आगे नहीं हो, क्योंकि वहाँ की जमीन समतल है, वहाँ की जमीन उपजाऊ है। नहर का निर्माण अगर इस प्रकार होगा कि जमीन के पानी बहने की व्यवस्था नहीं रहेगी तो वाटर लौगिंग का प्रोबलम होगा और जहाँ अभी फसल होती है वह जमीन बरबाद हो जायगी। इसलिये अभी से सरकार और सिंचाई विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ वाटर लौगिंग का प्रोबलम नहीं हो। लघु सिंचाई के संबंध में हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि लिफ्ट इरीगेशन होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जहाँ छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जिसमें पेरेनियल सोर्स औफ वाटर है, उससे लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर बिहार में छोटी-छोटी नदियाँ हैं जिनमें लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था आसानी से कम खर्च में की जा सकती है। नदी में पक्का बांध बांधकर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिये सरकार यदि ऐसी व्यवस्था करे तो सिंचाई में काफी लाभ होगा।

अब मैं टैक्स की चोरी के बारे में कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि पैसे की कमी है, इसलिये आर० ई० ओ० का काम नहीं हो रहा है और दूसरे-दूसरे आवश्यक काम नहीं हो रहे हैं। इसलिये आप टैक्स की चोरी की ओर ध्यान दीजिये। टैक्स की चोरी कैसे करते हैं। बड़े-बड़े व्यापारी भिन्न-भिन्न नाम से माल मँगाते हैं ताकि वे टैक्स से बच सकें। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार इसकी जाँच करावे, जो ऐसे व्यापारी हैं उनको सजा दे, ऐसा करने से राजस्व में वृद्धि होगा इसलिये सरकार इसका प्रबन्ध करे।

लेवी के विषय में हमारे कई साथियों ने चर्चा की है। लेवी के चलते लोगों में आज आतंक छाया हुआ है। गाँव में लेवी के नाम पर लूट हो रही है। अभी आपने बताया कि जिनके पास १० एकड़ तक जमीन है, उनको लेवी से छूट है। लेकिन लेवी की वसूली में क्या हुआ, किसानों को जितना लेवी देना था वह दे दिया, फिर भी, उनके घर से जबर्दस्ती अन्न उठाकर ले आया गया। फुलपरास में एक अब्दुल हुई हैं, उनके घर से सारा अन्न उठाकर ले आया गया और अभी तक उसका दाम भी नहीं दिया गया। अतः सरकार दाम देने की व्यवस्था करे। एक दूसरे गया प्रसाद साह हैं, उनके यहाँ कुल ४५ क्विंटल अनाज था, आपके बी० डी० ओ० पुलिस को ले जाकर सारा अन्न को ले आया। ये दोनों हमारे क्षेत्र की बातें हैं। हमारे भोला बाबू के क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। एक ओर सरकार कानून और विधि व्यवस्था की बात करती हैं और दूसरी ओर इस तरह होता है। किसान जो इतनी मिहनत से अन्न उपजाता है, उसे सरकार जबर्दस्ती उठाकर बिना कारण के ले आती है। ५० क्विंटल तक रखने की जो व्यवस्था है उसको भी ये उठाकर ले आते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो किसान लोग अपने बच्चों की शादी व्याह कैसे करेंगे, क्या खायेंगे।

अब मैं पुलिस व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। रेल में चलेंगे तो देखेंगे कि इनके जितने भी पुलिस हैं, चाहे स्कोर्ट हो या दूसरी पुलिस हो सारे लोग फर्स्ट क्लास में सो जाते हैं और जो सही फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर चलता है, उसको जगह नहीं देते हैं। सरकार कहती है कि पुलिस की सारी व्यवस्था हमने कर दी है। पुलिसवाले लोग राइफल लिये हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पुलिस या तो गठरीवाले से पैसा वसूल करते हैं या फर्स्ट क्लास में सो जाते हैं। इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य श्री अजीज्जुल हक ने सुगौली केन मार्केटिंग यूनियन के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा तो सरकार की ओर से कहा गया कि भ्रष्ट लोगों को सजा देंगे। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस पर सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की और उसका क्या अंजाम हुआ? उससे हमलोगों को राहत मिलेगी।

श्री मोती लाल सिन्हा कानन— सभापति महोदय, मैं द्वितीय अनुपूरक बजट का जोरदार समर्थन करता हूँ।

श्री भोला प्रसाद सिंह— सभापति महोदय, नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है।

श्री मोती लाल सिन्हा कानन— मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि लोक निर्माण मंत्री अभी मौजूद हैं और साथ-साथ पांडे जी भी मौजूद हैं। १० मार्च, १९७५ को इन्डियन नेशन के मौर्निंग एडिशन में एक रिपोर्ट छपी थी। "वंगलिंग ससपेक्टेड इन गंगा ब्रीज प्रोजेक्ट।" शायद इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। बहुत डिटेल में रिपोर्ट छपी है कि गंगा ब्रीज प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर लूट-खसोट चल रहा है। खास कर इस रिपोर्ट का महत्व बढ़ जाता है कि पिछले दिन लोक निर्माण मंत्री ने बहुत ही गौरवान्वित ढंग से घोषणा की कि गंगा ब्रीज प्रोजेक्ट का काम बहुत सन्तोषप्रद है और हमलोग सटिसफाइड हैं।

सभापति महोदय, इन्डियन नेशन में खास करके वोल्डर की खरीदगी, हाई टेन्शन स्टील की खरीदगी तथा ढलाई, खुदाई, सेटिंग वगैरह का पूरे डिटेल में आंकड़ा छपा है और इसकी रिपोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि २४ करोड़ रुपये में यह गंगा ब्रीज प्रोजेक्ट तैयार होनेवाला है। लेकिन जिस ढंग से बोगस विल का पेमेन्ट होता है और लूटखसोट चल रहा है, इससे उम्मीद किया जाता है कि चालीस-पच्चास करोड़ रुपया खर्च हो जायेगा तब यह योजना कम्पलीट होगी। इन्डियन नेशन के आरोपों के अलावे लगभग ११ आरोप मैं लगाना चाहता हूँ, जो निश्चित है। गंगा ब्रीज के उत्तरी अंचल के एस० ई० श्री रिजवी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में आजकल एडवांस प्लानिंग और डिजाइन में काम नहीं किया। लेकिन लगातार ये वर्क्स में ही रहे हैं और इनका कार्य क्षेत्र लूट-पाट का कार्यक्षेत्र नार्थ विहार का हाजीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के वीच में रहा है। इनका घर मुजफ्फरपुर में है। अभी छः महीना पहले गंगा प्रोजेक्ट से मुजफ्फरपुर ट्रांसफर इनका इनका हो गया है जहाँ इन्होंने १० लाख का मकान ब्रह्मपुर में बनाया है। गंगा ब्रीज के एस० ई० और मुजफ्फरपुर एडवांस प्लानिंग

के एस० ई० के रूप में रहने पर इनका लूट-पाट और भी बढ़ गया है। मैं यह निश्चित आरोप लगाता हूँ कि इन्होंने २ लाख का त्रिपाल खरीदा। मैं कहता हूँ कि एक त्रिपाल का लगभग ८० रुपया दाम मार्केट में है, लेकिन श्री रिजवी ने १०३५ रुपया इसके लिये तय किया है। एक श्री फुली मियाँ हैं, जो इनके अपने आदमी हैं। उनको विना टेन्डर के आर्डर दे दिया और उनको पेमेन्ट भी मिल गया, लेकिन आज तक वह माल खरीदा नहीं गया है। सभापति महोदय, दूसरा है वल्ले की खरीदगी तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग वाले, कोशी वाले जो दस रुपये में गल्ला खरीदते हैं उसी को इन्होंने ५० रुपया प्रति वल्ला फुली मियां से तय किया। यह ऑर्डर भी फुली मियां को विना टेन्डर के दिया गया है और वोगस पेमेन्ट लाखों रुपया का किया गया है। इसके वाद है विजली का समान, तो इस सम्बन्ध में हम कहना चाहते हैं कि मनमाने दर पर फुली मियां के द्वारा ही हाई रेट पर खरीदा गया। मैं कहूँगा कि उत्तरी अंचल में दो रुपये से लेकर दो लाख तक के लिये विना टेन्डर मांगे ही समान की खरीदगी मनमाने ढंग से अपने निजी लोगों के फायदे के लिये की गयी है जिसकी वजह से वहुत वड़ा लूट-खसोट हुआ है।

सभापति महोदय, इनके द्वारा जितने भी कार्य हुए हैं बरोजगार इंजीनियरों के नाम पर इन्होंने अपने निजी लोगों को बराबर काम दिया है। उत्तरी अंचल में जितनी भी ईंट लाखो रुपये की खरीदी गयी है स्पेसिफीकेशन के मुताविक एक या दो नम्बर की ईंट होनी चाहिये लेकिन कहीं भी जो ईंट खरीदी गयी है वो तीन नम्बर की ही है और तीन ही नम्बर की ईंट खरीदी गयी हैं और लगाये गये हैं। रिजवी साहेव ने रोड वनाने और मकान वनाने में जो रुपया खर्च किया है, वह गंगा ब्रीज डायभर्ट करके रुपया लिया गया है। जिस मकान में ये रहते हैं जो इनके दखल में हैं उसका रेन्ट पे नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि वे उसमें नहीं रहते हैं। ट्रेजरी वाले और ए० जी० ने भी पेमेंट के लिये इन्हें कहा है। परन्तु ये उस मकान का रेन्ट नहीं दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर एडवांस प्लानिंग और गंगा ब्रीज प्रोजेक्ट के डुएल चार्ज में रहने की वजह से महीने में दो हजार रुपये भत्ता के रूप में लेते हैं घर से जाने के लिये। इनकी गाड़ी का नम्बर है वी० आर० ए० १४००। ये वरावर अपने घर पर रहते

है और जो गाड़ी में पेट्रोल का खर्च होता है, वह सब गंगा ब्रीज के डिपो के नाम पर भाउचर बनता है और इनकी गाड़ी के नाम पर कभी भी पेमेंट नहीं हुआ है। गंगा ब्रीज का जो स्टाफ जीप है, वह काम में नहीं लाया गया है, लेकिन गंगा ब्रीज के जीप्स के नाम पर पेट्रोल का भाउचर्स लिया जाता है। मैंने ये आपको ११ आरोप बताया है। इसपर जाँच कराना आवश्यक है। बोल्डर के सप्लाई जो दक्षिणी अचल में १६३ रुपया १०० सी० एफ० टी० का निश्चित हुआ उन्होंने २५५ रुपये १०० सी० एफ० टी० हाई रेट पर दे दिया। कुल २८ लाख १०० सी० एफ० टी० बोल्डर मंगाने थे, लेकिन ३० लाख बोल्डर्स १०० सी० एफ० टी० का लिया गया जिससे २ लाख बच गया।

श्री रामस्वरूप राम— सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य का आरोप स्पेसिफीक जान पड़ता है तो अभी तक इसपर क्यों कारंवाई नहीं की गई।

सभापति (श्री कामदेव प्रसाद सिंह)— व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करते हैं।

श्री मोती लाल सिन्ह कानन— मैं चाहता हूं कि इन्डियन नेशन में जो छपा है, उसको पटल पर रख दूं। मैंने जो आरोप लगाया है, मैं चाहूंगा, अगर आप भ्रष्टाचार में कमी लाना चाहते हैं तो इसकी जाँच-पड़ताल के लिये माननीय सदस्यों की एक कमिटी बनायें। इसके लिये भवागन्द झा या सदन के कुछ मेम्बर्स उसमें रहें। चूंकि चौबीस करोड़ रुपये की बंगलिंग्स का प्रश्न है, इसलिये सरकार को इसमें शीघ्रतापूर्वक जाँच करानी चाहिये। अन्त में, मैं आपसे पूछता हूं कि ये छः महीने से बैठे हुए हैं क्यों ?

श्रीमती गायत्री देवी— सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नवादा जिला की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। यह जिला बराबर सूखा की चपेट में रहा है। सिंचाई की असुविधा के कारण यहाँ के किसान दाने-दाने को मुहताज हैं। आज से कुछ दिन पूर्व इस जिले में सिंचाई हेतु तिलैया डैम से नहर निकालने का विचार किया गया था, जो आज तक लम्बित है। अगर

इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से करवा दी जाय तो जिले का कुछ भाग अकाल की चपेट से सदा के लिये वंचित रह सकता है।

सभापति महोदय, जिले के लगभग ३०० गाँवों में विजली लगवाने के लिये सरकार ने योजना वनायी है, किन्तु आज तक इस योजना का दसांश भाग में भी सामान के अभाव में विजली नहीं लगायी जा सकी है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इसकी व्यवस्था यथाशीघ्र करवायी जाय।

सभापति महोदय, नवादा जिला में सड़क की नितान्त कमी है, जिसके कारण गाँवों का विकास नहीं हो रहा है। अत: लोक निर्माण मंत्री से मेरी आग्रह है कि सड़क की व्यवस्था करवा कर जिले की विकास के पथ पर लाने का प्रयास करें। नवादा प्रखंड के अन्तर्गत नवादा से नारदीगंज भाया कहुआरा सड़क १६७२ से ही सरकार के पास विचारार्थ है जिसका पक्कीकरण आज तक नहीं हो पाया है। इसी प्रकार नारदीगंज—पकरिया कच्ची सड़क एवं नवादा वाई-पास सड़क का निर्माण अतिशीघ्र किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त वातों पर जल्द-से-जल्द ध्यान दिया जाय।

सभापति महोदय, इस जिले को वने करीव दो वर्ष से भी अधिक हो गया है, किन्तु आजतक जिला शिक्षा पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं हो पायी है। जिला में शिक्षा का विकास हो, इसके लिये जिला स्कूल की व्यवस्था नहीं हो पायी है। आज से लगभग एक वर्ष पूर्व यहां श्री श्याम सुन्दर सिंह को जिला शिक्षा अधीक्षक के रूप में सेवा करने हेतु भेजा गया है। श्री सिंह पहले नवादा ट्रेनिंग स्कूल के प्राचार्य थे। जव तक वे प्राचार्य रहे वरावर राजनीति में रत रहे। जव इन्हें अधीक्षक के रूप में इसी शहर के अन्तर्गत पदस्थापित किया गया तव तो इनकी हरकतें और भी कई गुना अधिक हो गयी। इन्होंने दिन दहाड़े शिक्षकों से घूस लेकर प्राथमिक एव मिड्ल स्तर तक की शिक्षा को मखौल वना दिया है। शिक्षा मंत्री से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त वातों पर यथाशीघ्र ध्यान दें।

श्री महेन्द्र नारायण झा— सभापति महोदय, अभी सदन में केवल एक ही मंत्री हैं।

★**श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह**— सभापति महोदय, १९७४-७५ का वित्तीय अनुपूरक विवरण का जो प्रस्ताव माननीय मंत्री ने सदन में रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध करते हुए मैं कुछ नम्र निवेदन भी करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है जहाँ ७० से ७५ प्रतिशत लोगों का जीविकोपार्जन कृषि के द्वारा होता है और इसकी हालत बहुत ही रद्दी है साथ ही यहाँ कृषि को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मसलन मैं बतलाऊँ कि जब इस बार गेहूँ और मक्का का बीज किसानों ने मांगा तो सरकार के द्वारा कुछ तो पूर्ति की गयी समय पर, लेकिन ज्यादा बीज जनवरी महीना में आयी जबकि उस बीज की कोई आवश्यता नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि सरकार को बीज खरीदने के मद में करीब-करीब ८०-९० लाख रुपये की क्षति हुई है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बीज का प्रबन्ध नहीं कर सकती है। जब सरकार जानती है कि हमको हर साल उन्नत बीज मक्का और गेहूँ का यहाँ के किसानों को देना ही है तो अभी से, अप्रील महीने से, ही गेहूँ जो पैदा हो रहा है, उसी समय से बीज की आपूर्ति पर ध्यान क्यों नहीं देती है जिससे कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जितनी हमको आवश्यकता है, उसके मुताबिक बीज हम खरीदकर नेशनल सीड कारपोरेशन के गोदाम से या स्टेट फूड कारपोरेशन के गोदाम में सरकार क्यों नहीं जमा करती है ?

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि १९७४ में इतनी बड़ी बाढ़ आयी, जिसके बारे में कौन नहीं जानता है। हमारे सिंचाई मंत्री मुजफ्फरपुर गये, सीतामढ़ी गये और उन्होंने बागमती के तटबन्ध को बांधने के लिये रुपये भी मंजूर किया लेकिन लखनदेई के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। लखनदेई से बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से डूब गया था और बर्बाद हो गया था, लेकिन उस लखनदेई के तटबन्ध को बांधने के लिये अभी तक रुपया सैंक्शन नहीं हुआ है। हमलोगों ने सिंचाई मंत्री से कहा था कि आप उसके विभाग के द्वारा स्टीमेट बनवाइये और यह जो हार्ड मैनुवल स्कीम के लिये पैसा हैं, उसको लेकर सिंचाई विभाग के द्वारा इसको बनवा दीजिये। लेकिन अभी तक उसके लिये कुछ नहीं किया गया है और न सरकार इसपर किसी तरह से ध्यान देने को तैयार हैं।

अब मैं ट्यूबवेल की ड्रिलींग के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब हमारे चन्द्रशेखर बाबू मिनिस्टर थे तो उस समय एक रीग मशीन से एक दिन में एक ट्यूबवेल मशीन गरवा दिया जाता था लेकिन अब हालत यह हो गयी है कि अब ट्यूबवेल बैठाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इस विभाग के जितने भी पदाधिकारी है उनको तास खेलने के सिवा कोई काम नहीं रहता है। सरकार ने कानून बनाया है कि ११ हजार रुपया से १२ हजार रुपया सीड मनी जमा करने पर ट्यूबवेल बैठेगा। लेकिन सरकार ने हमारे यहां के किसानों को इस तरह से बेकार बना दिया है कि किसान सीड मनी देने को तैयार नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या आप अपने बजट से इस सीड मनी का भुगतान नहीं कर सकते हैं? अगर मान लीजिये कि आपके पास रुपया नहीं है तो प्लानींग कमीशन ने कहा है कि जिस क्षेत्र में मार्जीनल किसान होंगे जहाँ गरीब किसान होंगे और उनकी संख्या सैंकड़े ५० प्रतिशत से ज्यादा होगी ७५ प्रतिशत तक होगी तो उसके लिये सीड मनी की जरूरत नहीं है। वहाँ के सर्किल औफिसर एक सर्टिफिकेट देंगे वहां के डी० एम० सर्टिफिकेट देंगे कि उस क्षेत्र में सैकड़े ५० से ७५ प्रतिशत किसान गरीब और मार्जीनल हैं। यदि इस तरह से सर्किल औफिसर और डी० एम० सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उस इलाके में मंगनी में ट्यूबवेल बैठाया जा सकेगा और बैंक उसको एडभान्स करेगा। लेकिन आप कुछ करने को तैयार नहीं हैं।

यही हालत आपके इंडस्ट्रीयल बेल्ट की है। इंडस्ट्रीज के मामले में हालत यह हैं कि जहाँ उत्तर विहार को इस्फास्ट्रक्चर में रखा है और सीवान से लेकर पूर्णियाँ तक इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्पेशियली इन्डस्ट्रीयल बैकवार्ड डिक्लेयर किया है, वहाँ वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिला को उसमें सम्मिलित नहीं किया है।

भ्रष्टाचार आपके यहाँ परकाष्ठा पर है। हम आपसे अपील करेंगे कि आपने जिस तरह फर्टिलाइजर पर से कंट्रोल हटा लिया, उसी तरह चीनी पर से और सिमेंट पर से भी कंट्रोल हटा कर धीरे-धीरे प्रोग्रेसीव डिकंट्रोल कीजिये नहीं तो भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। हमारे लायक दोस्त माननीय सदस्यों ने कल

कहा था कि जय प्रकाश बाबू का आन्दोलन का खात्मा हो गया है और वे प्रतिक्रियावादी हैं। लेकिन सिर्फ जयप्रकाश बाबू की आलोचना करने से हमारा भ्रष्टाचार नहीं जायगा। मैं कहता हूँ कि आपके दिमाग पर जो लिखावट है, उसको पढ़िये और समझें और हमारे जितने मंत्रिगण हैं वे बैठकर अपने-अपने विभाग में प्रोग्राम बनावें कि कैसे काम किया जाय तब ही हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जय प्रकाश बाबू का जो आन्दोलन है, वह तीव्र गति से देहात की ओर बढ़ रहा है और जय प्रकाश कोई स्वार्थी नहीं हैं और वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपलोगों में जो त्रुटियाँ है, खामियाँ हैं, उसको दूर कर दें। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के दुश्मन नहीं है। वे आपके भीतर की खामियों को दूर करना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटा सकते हैं, जब तक कंट्रोल को हटा नहीं देते हैं। अगर आप कंट्रोल मिटा दें तो ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार अपने आप मिट जायगा। हम पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने निर्णय लिया हैं अपने यहाँ से कंट्रेक्टर को हटा देने का और विभाग द्वारा ही काम कराने का। यह बहुत ही उत्तम निर्णय लिया गया है। उससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार मिट जायगा।

अन्त में, मैं कहूँगा कि मेरे क्षेत्र में दरभंगा महाराज का बनाया हुआ काठ का पुल १८८५ से है और उसकी मरम्मती जमीन्दारी काल में हमेशा होती थी, लेकिन जमीन्दारी जब से चली गयी है, उसकी मरम्मती नहीं होती है। उसे बनाना अति आवश्यक है। अतः उसे बनाने का अनुरोध करके मैं बैठ जाता हूँ।

श्री मुहम्मद शकूर—सभापति महोदय, आपने पाँच मिनट का समय दिया है इसलिए मैं लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं करूँगा लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि यदि हमलोग इस बात की शपथ लेते हैं कि बिहार राज्य से भ्रष्टाचार को दूर करें, अनइम्प्लायमेंट को खातमा करें तो पहले इसके लिये जरूरी है कि हम आपसी नफरत को दूर करें। हमारे दिल में जो नफरत की भावना है उसको दूर करें तभी कुछ भलाई हम कर सकते हैं। दूसरी चीज है हवश। चाहे मंत्री

हों, चाहे विधायक हों सबों के दिल में हवश और नफरत की भावना जो रहती है उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक न तो देश की भलाई कर सकते हैं और न विहार राज्य की भलाई कर सकते हैं। आज नफरत है नन-मुस्लिम और मुस्लिम के बीच, नफरत है आदिवासी और नन-आदिवासी के बीच और नफरत है भूमिहार और नन-भूमिहार के बीच। इस नफरत को खतम करना होगा। जहाँ तक समस्याओं के हल करने का प्रश्न है मैं तमाम समस्या में नहीं जाकर केवल एक-आध समस्या की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। सरकार के दिल में सचमुच में समस्या को दूर करने के लिये मुहब्बत है तो आपने एक चीज को भी क्यों नहीं किया? दो-तीन साल से बराबर हमने इस बात का जिक्र किया कि भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में उर्दू शिक्षक नहीं है। लेकिन यह सरकार बिलकुल बहरी बनी हुई है। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। कितनी बार हाउस में चर्चा की गयी। इसलिये मैं जरूर चाहूँगा कि सरकार भाषण में इस बात का जिक्र करे। भागलपुर ट्रेनिंग कालेज में उर्दू शिक्षक नहीं है, राँची ट्रेनिंग कालेज में उर्दू शिक्षक नहीं है, तूर्की ट्रेनिंग कालेज में उर्दू शिक्षक नहीं है, पटना ट्रेनिंग कालेज में उर्दू शिक्षक नहीं है। इसलिए मैं, दो-तीन स्पेसिफिक ट्रेनिंग कालेजों के बारे में कहा। किन्तु अनेकों स्कूल और कालेज में उर्दू टीचर्स नहीं देते हैं। यह इसलिये करते हैं कि इनके दिल में नफरत है कि मुस्लिम बच्चे की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो। यही वजह है कि आप तमाम ट्रेनिंग स्कूलों और कालेजों में उर्दू शिक्षक को बहाल नहीं कर रहे हैं। यही नफरत की भावना है कि पटना मदरसा इस्लामिक बोर्ड जो है, जिसका कंट्रोल आप करते हैं और उसके ऊपर लाखों-लाख खर्च करते है परन्तु उस मदरसा इस्लामिक बोर्ड को एक टेलिफोन नहीं दे सके हैं। सभापति जी, मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को कई दफा उठाया है कि मदरसा इस्लामिक बोर्ड में दो पद खाली हैं। एक तरफ आप बेरोजगारी को मिटाने की बात करते हैं दूसरी तरफ जहाँ पद खाली हैं उसपर किसी की बहाली नहीं करते हैं। यह अजीब-सी बात है। उस दो पद में एक डाइरेक्टर का पद है और दूसरा सचिव का पद है, जो खाली है। एक पद के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकोमेंड करके नाम भी दिया, लेकिन उस फाईल को एजुकेशन मिनिस्टर लेकर बैठे हुए हैं।

मैंने इस बात का जिक्र किया कि वहाँ सचिव का पद खाली है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यह सैंक्शन पोस्ट है आप उसपर बहाल कर सकते हैं, लेकिन बहाली नहीं कर रहे हैं। गोली खाइयेगा, लतम-जूता खाइयेगा, जूते की माला पहनियेगा लेकिन इन पदों पर बहाली नहीं कीजियेगा। सभापति महोदय, मोतिहारी जिला स्कूल में उर्दू शिक्षक का पोस्ट खाली है, सरकार क्यों नहीं बहाली कर रही है? भागलपुर जिला स्कूल में उर्दू शिक्षक का स्थान खाली है लेकिन सरकार क्यों नहीं बहाली कर रही है? भागलपुर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में उर्दू शिक्षक का स्थान खाली है, गर्दनीबाग गवर्नमेंट हाई स्कूल में उर्दू शिक्षक का स्थान खाली है आप इन जगहों पर बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एडभरटीजमेंट करके बहाली कर सकते हैं लेकिन एडभरटीजमेंट क्यों नहीं करते हैं। सभापति महोदय, अगर दो तीन मिनट का समय और दे दें तो अच्छा होगा। सभापति महोदय, जो भाइटल प्रोब्लेम बिहार के लिये है वह गंगा से कटाव का है। पटना से लेकर मोतीहारी तक गंगा से कटाव होता है और सुरक्षा में लाखों-करोड़ों रुपये हर साल खर्च होते हैं। लेकिन जहाँ जाली में १०० बोल्डर देना चाहिये वहाँ इंजीनियर ५० बोल्डर ही डालते हैं जिसका नतीजा होता है वह गंगा की धार में बह जाता है उससे सुरक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस तरह ६ मील जमीन कट गयी है और कटाव रोकने में इस सरकार को कभी भी सफलता नहीं मिली है यह नापाक कोशिश है। सभापति महोदय, रिहेब्लीटेशन की समस्या सिर्फ हमारे ही क्षेत्र की नहीं है बल्कि यह प्रोब्लम सारे बिहार का है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है और कटाव से पीड़ित लोगों को बसाने की कारगर व्यवस्था नहीं करती है।

सभापति महोदय, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे। अभी इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में परचेज कमिटी है। उस परचेज कमिटी ने ६-३-७५ को जबकि ३१ मार्च, १९७५ को यह वर्ष समाप्त होने जा रहा है, पैसा खर्च करने जा रही है। बराबर लोगों ने कम्पलेन किया कि गाँवों में, घरों में बिजली वायर दीजिये लेकिन नहीं दिया गया और जो काम ६-७ महीना पहले करना चाहिये, नहीं किया। एक-ब-एक बंगलींग करने के लिए परचेज कमिटी ने ७० लाख रुपये का सप्लाई ऑर्डर दिया है। यदि आप बिहार के स्मौल स्केल इण्डस्ट्रीज की तरक्की

चाहते तो विहार के तमाम स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज से सप्लाई लेते। लेकिन भेस्टेड इंट्रेस्ट वाले लोगों ने पटना के एक-दो फार्म को ही ७० लाख रुपये का सप्लाई औडर दे दिया। अगर ऐसा ही करना था तो वाजाप्ता एडभरटीजमेंट करके टेंडर माँगते और वाजाब्ता सप्लाई लेते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इस सारे मामले की छानवीन शीघ्र करे।

श्री रामजतन पासवान— सभापति महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने इलाके की ओर आकृष्ट करता हूँ। हमारे इलाके की वात यह है कि दो प्रखंड सरकार को एसपेशल में करना पड़ा है। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। सवसे दुखद बात यह है कि हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री के एलेकसन के समय बहुत से मंत्री तरह-तरह के आश्वासन देकर जनता को आये थे लेकिन एक भी आश्वासन पूरा नहीं हो पाया। सभापति महोदय, यदि सरकार कमला वलान दरजिया से समस्तीपुर जिला के फुहिया करेह के बगिया तटबंध में मिला दे तो हम उतना अनाज पैदा कर सकते हैं कि विहार भर को खिला सकते हैं। हमारा इलाका इतना उपजाऊ है लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहाँ की हालत खराब है। वहाँ न सिंचाई की व्यवस्था है और न सड़क की व्यवस्था है, पता नहीं क्या कारण है। जनता में वहाँ काफी असंतोष है। जबतक उक्त वाँध जिसकी चर्चा ऊपर में मैंने की है, नहीं हो जाता है तबतक वहाँ बाढ़ कनट्रोल नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि विहार सरकार से यह संभव नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार की नीयत हमारे इलाके के संबंध में साफ नहीं है, लेकिन सरकार को समझना चाहिये कि जब कभी सरकार पर प्रतिक्रियावादी का हमला होता है तो किसान मजदूर ही सरकार की रक्षा के लिये तैयार रहते हैं। आज जनता में सरकार के कारनामे से काफी असंतोष है, कारण सरकार समय पर न बीज, न खाद और न बिजली की व्यवस्था कर पाती है। हमारे सिगया प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, वे लूट रहे हैं लेकिन चूँकि मंत्रिमंडल में उनके आदमी हैं। अतः वे वहाँ टिके हुए हैं। [× × ×] वे मंत्री के रिश्तेदार हैं

पाद टिप्पणी— [× × ×] अध्यक्ष महोदय द्वारा अपलोपित किया गया।

और मंत्री उनको छूट दिये हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसके बारे में जाँच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से जीतकर आता हूँ समस्तीपुर में और उस इलाके के अगल-बगल एक भी सड़क नहीं है। आने-जाने की कोई सुविधा नहीं हैं। इसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखकर दिया और माननीय मंत्री श्री बैठा जी को दिया लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आजतक वहाँ आवागवन की कोई सुविधा नहीं है।

श्री महेन्द्र नारायण झा— सभापति महोदय, द्वितीय सप्लीमेंटरी बजट जो सदन में पेश है उसका मैं समर्थन करता हूँ और अभी की जो स्थिति है उसकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। हमारे मित्र त्रिवेणी बाबू ने कुछ ऐसा प्रश्न उठाया है जिससे मालूम पड़ा कि कोई भी आदमी जो जनतंत्र का प्रेमी है, संसदीय व्यवस्था में विश्वास करता है ऐसे मौके पर इस बात की सफाई में भी कम-से-कम उनकी बातों को कैसे स्वीकार कर सकता है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ धर्म का निर्वाह करना चाहिए। त्रिवेणी बाबू ने जय प्रकाश बाबू की क्रांति की बात की है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें कोई वैर नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि त्रिवेणी बाबू मेरी पार्टी की वकालत नहीं करते तो अच्छा होता। जय प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी और इन्दिरा गांधी तथा जनतांत्रिक व्यवस्था को देश से समाप्त कर करोड़ों जनता की आशा और आकांक्षा को समाप्त करना चाहते हैं। आज ऐसी परिस्थिति हो गयी है कि जनतंत्र पर बादल घिरा हुआ है। जय प्रकाश बाबू जनतंत्र की वकालत करके जनता की गला घोंटने वालों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक जय प्रकाश जी हों या कोई हों आज जिस तरह से समाज आगे बढ़ना चाहता है, उसे बढ़ने न देकर समाज को पीछे की ओर धकेलना न किसी को वह शक्ति है और न समाज की उसे स्वीकृति मिल सकती है। महोदय, जय प्रकाश बाबू रेल के पटरी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं छोटी लाइन को बड़ी लाइन नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि रेल की पटरी को उखड़वा देना चाहते हैं। जय प्रकाश बाबू को त्रिवेणी बाबू जो समझते हों, लेकिन यहाँ के सभी माननीय सदस्य भी उन्हें अच्छी तरह समझते हैं।

महोदय, अभी की स्थिति में कल्ह इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो घटना घटी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए सदन में सरकार की ओर से निन्दा का प्रस्ताव आने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबी को मिटाने के लिए समाजवाद के लिए जिस तरह से बेचैन हैं, इसे सभी जानते हैं। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने नरीरा प्रोग्राम बनाकर जल्द-से-जल्द ग्रामीण जनता और खासकर कमजोर और उपेक्षित वर्ग के लिए निश्चित अवधि के अन्दर कालबद्ध कार्यक्रम बनाकर जल्द-से-जल्द लागू कराकर जनतंत्र के प्रति तथा कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करना चाहती है। श्रीमती गाँधी वास्तव में सर्वोच्च नेता एवं जनतंत्र के प्रहरी के रूप में कारगर कदम उठाना चाहती हैं। उन्होंने दिल्ली में कहा था कि श्री ललित नारायण की हत्या एक रिहरसल है। महोदय, आज की स्थिति में जो घटना घटी है उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि देश के अन्दर, दुनियां के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं वे एक जुट होकर आजमाइश करना चाहती हैं। दुनिया के अन्दर जनतंत्र में, संसदीय प्रणाली में काफी लोगों की आस्था हो चुकी है और उसके खतम करने के लिए एकमात्र प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्रतिक्रियावादी शक्ति हत्या करने के लिए काफी सक्रिय और एक जुट हो चुकी है जो चिन्ता का विषय है और उसकी निन्दा की जानी चाहिए। इसलिये मैं चाहता हूँ, चाहे वह आदमी बहुत निराश रहा हो, चाहे वह किसी प्रभाव में आकर ऐसा किया हो, लेकिन वह पकड़ में आ गया। उसकी मंशा सफल नहीं हुई। इसलिये इस सदन में तत्काल इसकी निन्दा होनी चाहिये। हमारी मांग है कि सदन की भावना को देखते हुए सरकार यह प्रस्ताव पेश करे और वहां पहुँचाये। इस तरह के षडयंत्र के बारे में निन्दा होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूँ। अमेरिका द्वारा पहले की सारी बातों को याद कराने के लिये पाकिस्तान को पुनः हथियार देने की बात है। हमारे देश की सरकार ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया, उसको अनसुनी करके हथियार पाकिस्तान को देने जा रही है। इसके पीछे षड्यन्त्र है और श्री जय प्रकाश नारायण उनके सम्बन्ध में अपना स्वर मुखरित करते हैं।

आपने देखा होगा कि उनका जो प्रदर्शन पटने में हुआ, उसमें पाँच हजार से १० हजार व्यक्ति आये हुए थे। वे वैसे ही लोग थे जो कि पटने के ही थे और उनके दवाव में आकर आये हुए थे। पाकिस्तान सोचता है कि श्री जय प्रकाश नारायण का जो कुचक्र हैं, वह सफल हो जाय और वह इसको वल देना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस वात की निन्दा की जाय कि हथियार देने की जो साजिश हो रही है, वह अमेरिका का गलत कदम है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सदन की भावना को देखते हुए दोनों प्रस्ताव सरकार की ओर से आवे और उसे सर्वसम्मति से पास कर भेज दिया जाय।

श्री सूरजदेव सिंह— सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सिंचाई की असुविधा हैं, दिक्कत है जिससे लोगों को काफी परेशानी है। इसकी वजह से काफी दिक्कत उनलोगों को हो रही है। वहाँ पर सूखे की स्थिति का एक खास कारण यही है, लेकिन सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। फलगु नदी से एक पड़न निकला है जिसकी सफाई करने के लिए मैं पहले कहा था। अगर उस पड़त की सफाई हो जाती तो वहां सूखे की स्थिति नहीं आती। जमींदारी जाने के वाद आज तक सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया है। सरकार का ध्यान मीलाटांर, चिरैयाटांर की ओर नहीं गया है। मीलाटांर पड़त पर एक लाख ८ हजार खर्च किया गया था और खर्च करने के वाद उस काम को वन्द कर दिया गया। उसके बाद उसका रिभाइज्ड एस्टीमेट वना और उसके वाद भी वह खटाई में पड़ा हुआ है। वात समझ में नहीं आती है कि सरकार का ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं जाता है। ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा जो सड़क बनाई जाती है, उनमें भी गड़वड़ी है। हमारे क्षेत्र की एक सड़क है जिस पर रद्दी मेटेरियल्स रखा गया है। आप इसकी जाँच करावें कि उस मेटेरियल्स से रोड वन सकता है या नहीं? अव मैं सरकार का ध्यान बिजली विभाग की ओर ले जाना चाहता हूँ। बिजली बोर्ड से एक नियम निकाला गया है विजली कनेक्शन देने के सम्बन्ध में। वह वकाये के भुगतान के सम्बन्ध में है। अगर कहीं डिनकनेक्शन हो जाता है वकाये के सिलसिले में और १५ आदमी उससे सम्वन्धित है, उसमें से १४ आदमी भुगतान कर देता है एक आदमी नहीं देता है तो कनेक्शन नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ

कि बिजली बोर्ड का यह नियम ठीक नहीं है और उसको चाहिए २४ घंटे के अन्दर कनेक्सन दे दे। इसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके सम्बन्ध में बिजली बोर्ड को डाइरेक्शन दे, आदेश दे कि अगर किसानों द्वारा बिजली के बिल का भुगतान कर दिया जाय तो उसको कनेक्शन दे दिया जाय। हमारे क्षेत्र के वजीरगंज के लोगों ने १९६७ में बिजली कनेक्शन के लिए पैसा जमा किया लेकिन आज तक उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। मैंने कई बार इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन सरकार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया।

अब मैं सरकार का ध्यान पी० डब्लू० डी० की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैंने खनन् मंत्री का ध्यान एक प्रश्न के द्वारा आकर्षित किया था कि एक सड़क जो रजौली में है, उसको पक्कीकरण किया जाय। लोक-निर्माण विभाग द्वारा अर्थ वर्क कम्पलीट हो गया है तो पक्कीकरण कराने में क्या दिक्कत है। मैं विभाग को बतला देना चाहता हूँ कि अन्य सड़कों में जितना खर्च पड़ता है उसका एक चौथाई खर्च विभाग का होगा। खनन् विभाग ने कहा है कि दो हजार प्रति वर्ष इस खनन् से आमदनी होती है लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि २० हजार प्रतिवर्ष इससे आमदनी होती है। मैंने सरकार से आग्रह किया था कि इस रोड को पक्की करावें तो उत्तर मिला कि इससे सिर्फ दो हजार रुपये प्रतिवर्ष आमदनी होती है। इसलिये पक्कीकरण नहीं किया जा सकता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार इस रोड का पक्कीकरण करा दे।

श्री सोम मुरमू— सभापति महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और इस सिलसिले में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि संथाल से संथालपरगना का नामकरण हुआ था। हाल की एक घटना है कि वहाँ के जंगल का बाघ था जिसको गोपीकन्दर थाना के मनुहेम्ब्रम परगनाइत ने मार दिया। इसके लिये उसका बन्दूक सीज कर लिया और एक हजार जुर्माना किया गया। उसी तरह शिकारीपाड़ा थाना के कमराटांड गांव के बेनजामीन हंसदा को नजर बन्द कर दिया गया। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि

आदिवासियों के माल-जान को क्षति पहुँचाने वाले बाघ को यदि नहीं मारा जायगा तो आदिवासी कैसे रह सकते हैं। आदिवासियों को शिकार करने के अभियोग में नजरबन्द किया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ और सिचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि संथालपरगना में सिंचाई की कोई योजना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सिंचाई योजना के सम्बन्ध में जो सजेशन देते हैं उसमें एक को भी कार्यरूप नहीं दिया जाता है। कई बार हमलोगों ने सुझाव दिया कि वहाँ जो छोटे-छोटे नाले हैं उसको बांध कर पम्पिग सेट के द्वारा खेतों में पानी पहुँचाया जा सकता है। लेकिन सजेशन देने के बाद भी सरकार उलटा काम करती है। वहाँ बड़ी-बड़ी सिंचाई योजना सरकार बनाती है जिससे आदिवासियों के खेत डूब जाते हैं। इसलिये सरकार से कहूँगा कि हम लोगों के सुझाव पर ध्यान दे दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के २७ वर्षों के बाद भी संथालपरगना में २७ मील तक भी सड़क नहीं बनी है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि दुमका से रामगढ़ और आमलापाड़ा से पाकुर तक जो रोड है, वह नहीं बनाया जा रहा है। आप बराबर कहते हैं कि इसको बना देगें। लेकिन जब हमलोग जिला पर्षद् से पूछते हैं तो कहा जाता है आवंटन नहीं है। इस तरह सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और अंत में कह दिया जायेगा कि आवंटन नहीं है। इसलिए मैं सरकार का विशेष ध्यान इस ओर खीचता हूँ।

श्री जयप्रकाश मिश्र— सभापति महोदय, मैं समय की कमी की वजह से सिर्फ अपने क्षेत्र की बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरा क्षेत्र कटोरिया और बौसी भागलपुर में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और अगर इनकी तुलना संथालपरगना और छोटानागपुर से की जाय तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। वहाँ सिंचाई का समुचित प्रबन्ध नहीं है। वहाँ लघु सिंचाई योजनाएं सफल हो सकती है, लेकिन उनकी अवहेलना की जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सदन में घोषणा की कि लीफ्ट ऐरिगेशन कारपोरेशन बनाया जा रहा है और उसमें भागलपुर के ऐसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जायगा और इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। सभापति महोदय, हरित क्रान्ति की बात कही जाती है, लेकिन

हरित क्रान्ति तभी सफल हो सकती है जब सिंचाई का समुचित प्रबन्ध हो। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत सी इस तरह की योजनाएँ है जो विभागीय संचिकाओं में वर्षों से पड़ी हुई है और जिनसे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती थी। सभापति महोदय, सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएँ ऐसी है जिन्हें स्वीकृत की जा चुकी है, परन्तु अभी तक उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। भितिया बांध की योजना आठ वर्षों से सचिवालय में जाकर पड़ी हुई है। कुछ दिन पहले जनवरी माह में लघु सिंचाई विभाग का प्रतिवेदन हुआ कि इसकी प्राक्कलित राशि अधिक हो गई है इसलिये इसका कार्यान्वयन लघु सिंचाई विभाग नहीं करेगा और इसे सिंचाई विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया। जब संचिका सिंचाई विभाग में पहुँची तो सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता ने यह लिखा कि लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन और रूपांकन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आश्चर्य की बात है ऐसे मामले में किस प्रकार सिंचाई विभाग लघु सिंचाई विभाग से अधिक काबिल हो जाता है। सभापति महोदय, सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग में कोआर्डिनेसन नहीं है और इसके बिना काम ठीक नहीं चल सकता है। अब मैं आपका ध्यान विद्युतिकरण की ओर ले जाना चाहता हूँ। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने के लिये बिजली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इससे सिंचाई की व्यवस्था अधिक-से-अधिक की जा सकती है, परन्तु देखा यह जाता है कि बिजली का उपयोग शहरों को सजाने में किया जाता है। किसान बिजली लाइन के लिये प्रयास करता है, लेकिन उनको बिजली नहीं दी जाती है।

अब मैं पैडी लेवी के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकारी आदेश है कि वैसे आदमी पर लेवी लगेगा जिसके पास ५ एकड़ से अधिक जमीन हो, लेकिन गत माह कटोरिया थाने के धावा ग्राम से झम्मन महतो के यहाँ से एस० डी० ओ० सारा अनाज ले लिया जबकि लेवी नोटिस के अन्दर वे नहीं आते थे। मैं कहूँगा इनके अधिकारी सरकारी आदेश की अवहेलना करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

श्री तुलसी राम— सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। सरकार ने जनता की सुख-सुविधा के लिये बड़े जिलों को कई भागों में बांटा है। चकिया एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसे सवडिविजन वनना चाहिये था और इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की थी। माननीय सदस्यों की एक बैठक में राय मांगी गयी थी तो मैंने कहा था कि मोतीहारी जिले के लिये इसको सवडिविजन बनाना आवश्यक है, लेकिन भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री केदार पांडेय ने बिना एम० पी० तथा एम० एल० एज० की राय के सिकरहना को सवडिविजन बनाया और मुख्यालय इसका ढाका में रखा। इसलिये वहाँ की जनता क्षुब्ध है। मैं मांग करता हूँ कि चकिया तथा मधुवन को सदर अनुमंडल में रखा जाय।

विहार में ८० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। यदि सरकार किसानों को समय पर बीज, खाद तथा सिचाई की सुविधा दे, स्थायी तौर पर पानी पहुँचाने का प्रवन्ध करे तो उपज बहुत बढ़ जायगी इसलिए मैं मांग करता हूँ कि दूर-दूर तक पानी पहुँचाने के लिये फिल्ड चैनल बनाये जायें। किसानों ने बोरिंग करा लिया है लेकिन बिजली के अभाव में वे सिचाई नहीं कर पा रहे है। इसलिये जल्द विजली देने का प्रवन्ध किया जाय। जहाँ नहर से पानी नहीं दिया जा सकता है वहाँ राजकीय नलकूप शीघ्र बनाये जायें।

श्री सत्य नारायण सिंह— सभापति महोदय, द्वितीय अनुपूरक बजट जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और साथ-ही-साथ यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग प्रजातंत्र बचाओ का नारा देते हैं, कहते हैं कि आज प्रजातंत्र खतरे में है, इसे बचाओ। राजा बिंबिसार के समय में वैशाली भी एक रिपवलिक था। पूरा प्रयत्न करने पर भी जब बिंबिसार उसे खतम नहीं कर सका तो वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर इसको खतम करने का उपाय पूछा। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द को बुलाकर कहा कि जाकर पता लगाओ कि वैशाली के लोग आपस में नेता बनने के लिये लड़ते हैं कि नहीं। आनन्द ने पता लगाकर कहा कि सारी जनता एक नेता के इशारे पर चलती है विश्वास के साथ। तव बुद्ध ने बिंबिसार को वताया कि कोई उपाय नहीं है। तुम वहाँ

जाकर लोगों में नेता बनने के लिए फूट डालो, तभी तुम सफल होगे। इसलिए आज मैं प्रजातंत्र का हामी भरनेवालों से पूछता हूँ और खासकर ट्रेजरी बेंच के लोगों से कि क्या वे एक नेता को पूरे बिहार के हित में काम करने देने के लिये तैयार हैं? हर व्यक्ति सोचता है कि मंत्री नहीं बनूँगा तो सरकार को चलने ही नहीं दूंगा।

डेमोक्रेसी कमजोर रहेगी। डेमोक्रेसी जिन्दा नहीं रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि देश और प्रदेश की जनता को सबसे प्रिय उनकी इज्जत और माल है और अगर आप उनकी इज्जत और माल को नहीं बचा सकते हैं तो आप सरकार कहलाने लायक नहीं हैं। धनबाद में दिन दहाड़े गोयल ट्रेडिंग कम्पनी को ९-३-७५ को लूट लिया गया। जालान के लड़के को जान मारने की साजिश की गयी। हमारे घर में भी डकैती हुई जिसका जिक्र मैंने असेम्बली में किया, लेकिन आज तक एक भी क्रीमीनल को नहीं पकड़ा गया जिसमें टी० आई० परेड में एक भी नहीं पहचाना जा सके।

दूसरी बात है कि आज रामराज की बात की जा रही है और राम राज की परिभाषा होती है—

"दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा।"

इसका मतलब होता है कि शारीरिक, संसारिक और दैविक दुःख किसी को न हो। मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं है, कम-से-कम जनता को सुख आप दे सकें वही आप दें। आप सिर्फ अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन इसका असर किसी पर नहीं पड़ता है क्योंकि आपका आचरण स्वयं ठीक नहीं है।

आप करप्शन की बात करते हैं, करप्शन भाषण देने से नहीं मिटेगा, उपदेश देने से नहीं मिटेगा। कहा भी है कि—

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे।"

यह महसूस करने की बात है, कहने की बात नहीं है। ३१८ एम० एल० ए० इनक्लूडिंग मंत्री आज प्रतिज्ञा कर लें कि कोई गलत काम नहीं करेंगे तो

३१८ में सुधार हो जाने से प्रशासन करनेवाले अधिकारी आप-से-आप रास्ते पर आ जायेंगे। आपका मोरल ऊँचा होने से उनका भी मोरल ऊँचा हो जायगा।

मैं बताऊँ महात्मा गांधी जी से जब लोग पूछा करते थे कि आपके साथ आने से क्या मिलेगा तो महात्मा गांधी कहते थे कि दुख, प्यास, जेल, गोली, आदि-आदि चीजें मिलेगी। फिर भी, ४०-४५ करोड़ जनता उनके साथ रहती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को खाना और पानी नहीं देते हैं तो रामराज के सपना की बात क्या करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जनता दिल से हमारी साथ हो तो आपको अपना आचरण शुद्ध करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिये कुछ कर सकती है। इसलिये कांग्रेस को हिम्मत से काम लेना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा देवी—सभापति महोदय, आज बिहार की स्थिति के बारे में हम लोग सदन में कई दिनों से विचार करते रहे हैं। मैं इससे संबंधित एक दो बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अभी बिहार में जो लॉ ऐंड आर्डर की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, इससे हम, आप और सभी लोग अवगत हैं। मैं भोजपुर जिला के तरारी प्रखंड के धनगाई गांव के एक व्यक्ति के बारे में कहना चाहती हूँ जो वहाँ के मुखिया हैं और ये मुखिया उच्च जाति के हैं। उनके खलिहान में आग लग गयी और उनका गल्ला जल गया। इस पर उन्होंने इसका पता लगाने के लिये कि आग किसने लगाई, एक ज्योतिषी से पूछने के लिये गये। उस ज्योतिषी ने एक लक्ष्मण प्रसाद का नाम ले लिया। तो उस मुखिया ने घर आकर लक्ष्मण प्रसाद के गले में दोनों तरफ से लाठी लगा कर मारने की कोशिश की। लेकिन गाँव वालों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधकर्मी के कुकर्म के साथ वहाँ के दारोगा भी है। और जब लक्ष्मण प्रसाद को छोड़ दिया गया तो मुखिया ने एक कागज २६,००० रु० का लिखवा लिया। और दारोगा इस सारे कामों में मुखिया का साथ दे रहे हैं। उस गरीब का कोई सहायक नहीं है। एक ध्यानाकर्षण सूचना भी मैंने दी है लेकिन उसका जवाब नहीं आया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुजफ्फरपुर जिले के कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुर रोहतास में बसे हुए हैं। इसी तरह दूसरे-दूसरे जिलों में भी

लोग वसे हुए हैं, ऐसे लोगों से धान, गेहूँ और चावल की वसूली की गयी और बड़े-बड़े किसानों के घर तालाबन्दी कर दी गयी। २६ अप्रील १९७३ को ग्राम पीपरा विसो, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर के श्री राम वहादुर प्रसाद के यहाँ छापा मारा गया और २५ क्वींटल गेहूँ, ६५ क्वींटल धान, २० क्वींटल मकई जप्त किया गया। आज दो वर्ष हो गये कोई सरकारी निर्णय नहीं लिया गया जिसके कारण जब्त किया गया अनाज सड़ गया। इससे न तो बड़े किसान श्री राम वहादुर प्रसाद को लाभ हुआ और न गरीव जनता को लाभ हुआ। वल्कि राम वहादुर प्रसाद को काफी क्षति हुई। इसी तरह दो और तीन मार्च, १९७५ को जिला रोहतास के करगहर प्रखंड के गाँव सिलारी के श्री द्वारका चौधरी, सिवान के श्री सोमनाथ सिंह, डिमियों के श्री वासुदेव पांडे, लहेरी के श्री बैजनाथ सिंह, सेलाश के श्री जगनारायण सिंह और इन्दौर के श्री राम प्रसाद चौवे के यहाँ छापा मारा गया और करीव ७०० क्वींटल धान, चावल और गेहूँ जप्त किया गया और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सरकार इस पर शीघ्र ध्यान दे।

दूसरी वात अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के वारे में कहना चाहती हूँ। यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहती हूँ कि हर व्लौक में एक आवासीय कन्या विद्यालय खोला जाय। यदि मैट्रीक तक न हो सके तो मिड्ल तक ही खोला जाय ताकि गाँव की लड़कियाँ शिक्षित हो सकें।

दूसरी वात में और यह कहना चाहती हूँ कि अव ज्यादा नहीं तो सचिवालय में १० प्रतिशत महिलाओं के लिये नियुक्ति के लिए सीट रिजर्व करें। रेलवे और दूसरे-दूसरे सभी विभागों में भी इसकी आवश्यकता है।

विजली और सिंचाई के वारे में कहना चाहती हूँ कि यदि आप गाँव की आर्थिक हालत सुधारना चाहते हैं तो गाँवों में ट्यूववेल और विजली की व्यवस्था करें। अगर यह काम कर देंगे तो लोग खुद सिंचाई कर लेंगे। साथ-साथ एक काम और कीजिए। पटना में हर जगह सिलाई मशीन की व्यवस्था कीजिए। छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज की व्यवस्था कीजिए और यहाँ के महिलाओं को

उसमें काम दीजिए ताकि पटना की महिलाएँ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें।

श्री दारोगा प्रसाद राय— माननीय सभापति महोदय, विधान परिषद् में व्यस्त रहने के कारण मैं माननीय सदस्यों के भाषण को नहीं सुन सका, लेकिन जो कुछ नोट हो सका है·· ·· ··

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्क्ष— नोट नहीं कर सके हैं या नहीं सुन सके हैं तो सभी स्पीच को ले लीजिए और उसके अनुसार कार्रवाई कीजिएगा।

श्री दारोगा प्रसाद राय— जो थोड़ा बहुत हमारे साथियों ने नोट किया है, वह हमारे सामने है। कल्ह भी मैंने बताया था कि यहाँ के ९० प्रतिशत लोग गाँव में हैं। इसलिये गाँव की स्थिति जब तक नहीं बदलेगी तब तक कोई भी स्थिति बदलनेवाली नहीं है और इसके लिये यह सरकार दृढ़ संकल्प है कि किस तरह से खेती की पैदावार बढ़ाई जाय, इसके लिये रसायनिक खाद का प्रबन्ध किया जाय। हमारी यह भी कोशिश है कि स्थानीय शहरी खादों को हम किस तरह से बढ़ावें। हमारी यह भी कोशिश है कि दो-तीन वर्षों में ज्यादा-से-ज्यादा तायदाद में हम गाँवों तक उत्तम बीज पहुँचा दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि और चीज खेती की जैसी भी रहे लेकिन उन्नत बीज दे दिया जाय तो खेती की पैदावार १५ से २० प्रतिशत तक बढ़ सकती है जो अब तक हमलोग नहीं कर सके हैं। फिर भी, इस साल में सरकार ने सबसे ज्यादा बीज बांटा है। दो-तीन माह में सब जगह सब किसानों के पास उत्तम बीज पहुँच जाय इसके लिये सरकार की तरफ से हर सम्भव प्रयास किया जायगा। साथ ही सरकार की यह भी कोशिश रहेगी कि समय पर उन्नत बीज पहुँचे। खाद की स्थिति भी अब काफी सुधरी है। इसका कारण यह भी है कि देश में फर्टिलाइजर प्लान्ट की संख्या बढ़ रही है। गांव की हालत सुधारने के लिये सरकार का क्या इरादा है, सरकार की क्या मंशा है, इसको आप इसी से अन्दाज लगा सकते हैं कि अभी जो हमारा बजट है, उसका ७० से ८० प्रतिशत हम ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को दुरुस्त करने में खर्च करने जा रहे हैं। अगर रुरल रोड्स को ले लें जो आर० ई० ओ०

के द्वारा हो रहा है, यह सब मिलाकर बजट का ८३ प्रतिशत हम ग्रामीण व्यवस्था में लगाये हुए हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि इससे हमारी सारी ग्रामीण समस्या हल हो जायेंगी। यह हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका, जापान में भी जो इतना आगे बढ़ गया है, वहां भी सारी समस्या अब तक हल नहीं हो पायी है। लेकिन मैं इतने दिनों के अनुभव के बाद देख रहा हूँ कि जो समस्या हम आम तौर से मानते हैं, वह दो-तीन वर्षों में हल हो जायगी। आज सभी जगह बिजली की माँग की जाती है, पानी की मांग की जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गाँव की जो सड़कें हैं, वह ऐसी कम-से-कम हो जाय कि सालों भर आने-जाने लायक रहे, भले ही पीच न हो सके। फिर भी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण सड़कों की संख्या भी काफी बढ़ी है। कुछ को छोड़कर अधिकांश सड़कें आर० ई० ओ० के अन्दर आ गयी हैं। ६५ हजार गाँवों में हमें बिजली पहुँचानी है जिसमें से अभी सिर्फ आठ-दस हजार गाँव में ही बिजली पहुँचा सके हैं जबकि दूसरे कई राज्यों में यह काम हो गया है। कभी-कभी मुझे लगता है कि इस रफ्तार से यह काम करने में बहुत दिन लगेगा लेकिन मुझे एक बात सोचकर सन्तोष भी होता है कि अब काम में प्रगति होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब कामों का शुरुआत हो गया है और इसको शुरू करने में जिन-चीजों की जरूरत थी वह सब पूरा कर लिया गया है और जो बाधाएँ थीं, वह भी दूर हो गयी है। इसलिये मुझे विश्वास है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मान लिया कि कोई पत्थर तोड़ रहा है और ९९ चोट पत्थर पर मार चुकने के बाद भी लोग देखते हैं कि पत्थर नहीं टूटा है तो उसपर लोग क्षोभ प्रकट करते हैं, लेकिन वही आदमी जब सौवां चोट मारता है तो पत्थर टूट जाता है, वही हालत आज हमारी है। इस तरह से हमारे काम का भी रिजल्ट मैजिक की तरह एक-ब-एक हो जायगा। सभी बातों का जवाब देने का समय नहीं है, लेकिन हमारे एक-दो दोस्त ने उर्दू शिक्षक की बहाली की बात कही। यह दुःखद बात है। पहले भी उर्दू स्कूल में हिन्दी-नोइंग टीचर बहाल कर लिये जाते थे, लेकिन मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि सरकार इसपर ध्यान देगी।

श्री अम्बिका प्रसाद— उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय शिक्षा मंत्री ने इसी सत्र में कहा था कि ५० कालेजों को अंगीभूत करने जा रही हैं

सरकार लेकिन आज "आर्यावर्त" में निकला है कि इसे अंगीभूत करने के लिये सब-कमिटी सरकार ने बना दी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब-कमिटी को यह अधिकार है कि वह मंत्री की घोषणा के वाद भी उसको वदल दे।

श्री दारोगा प्रसाद राय— उपाध्यक्ष महोदय, कल्ह भी तो उत्तर देना है, आज समय की कमी है इसलिये अब माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया है, उस पर कल्ह जवाव दिया जायगा और यदि नहीं हो सका तो उन सब सुझावों को सरकार नोट करके उसपर कार्रवाई करेगी, इतना मैं आश्वासन सदन को देता हूँ।

श्री रघुनन्दन प्रसाद— उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राधानन्दन झा ने जो प्रश्न उठाया है, उसका जवाव तो दिलवा दिया जाय।

श्री दारोगा प्रसाद राय— अब पाँच वज रहा है, उसपर कल्ह जवाव दिया जायगा।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

राज्य मंत्रीगण कार्यालय व्यय के लिये २,५०,००० रुपये का उपबन्ध लोपित किया जाय।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

"द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के ३ से ५, १२ से २३, ३९ से ४१ एवं ८५ से ८७ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिये मंत्री परिषद्, निर्वाचन, सचिवालय एवं जिला प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा विहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त २,३८,३६,९०५ रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)